

**सोने एवं चांदी
आभूषणों
के विक्रेता**

माँ दुर्गा ज्वेलर्स

उचित व्याज में गिरवी रखी जाती है

शॉप नं. 69, सी-मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई
मो. 9424124911

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

**प्लिंट और डीजिटल मीडिया
में सभी प्रकार के
विज्ञापन के लिए**

संपर्क करे
9303289950
7987166110

वर्ष- 17 अंक - 243 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, मंगलवार 16 जून 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

छत्तीसगढ़ में मानसून पर ब्रेक, एंट्री से पहले थमी रफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है और यह प्रदेश की दहलीज पर आकर अटक गया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। कई जगहों पर 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ भी चल सकता है। पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवा चली और बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गईं। वहीं प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड हुआ।

यूएस-ईरान समझौते के बाद होर्मुज से जल्द निकलेंगे 34 भारतीय जहाज

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित होगी। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। दरअसल तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) ला रहे भारतीय टैंकर दिशा ने सुरक्षित होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर लिया है। भारत आ रहे 34 अन्य जहाजों के भी जल्द होर्मुज पार करने की उम्मीद है। ये जहाज पश्चिम एशिया संकट के चलते होर्मुज में फंसे हैं। होर्मुज में फंसे 34 जहाजों में से 16 जहाज ऐसे हैं, जो फर्टिलाइजर लेकर भारत आ रहे हैं। इन 16 जहाजों में से 8 पर यूरिया, चार पर डाइ-अमोनियम फॉस्फेट और तीन पर सल्फर और एक पर अमोनिया लदा है। अगर समझौते के तहत सबकुछ सही रहता है और होर्मुज खुलता है तो जल्द ही भारत के करोड़ों किसानों को खेती के लिए फर्टिलाइजर मिल सकते हैं।

छत्तीसगढ़ी युवा सिंगर 'एप्पी राजा' का निधन

भानुप्रतापपुर। छत्तीसगढ़ के संगीत जगत से एक दुःखद खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ी रैप संगीत को नई पहचान दिलाने वाले युवा कलाकार चेतन चांडक उर्फ एप्पी राजा का लंबी बीमारी के बाद रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया। उनके असाध्यिक निधन से संगीत प्रेमियों और युवाओं में शोक की लहर दौड़ गई है। एप्पी राजा छत्तीसगढ़ के शुरूआती रैप सिंगरों में शामिल थे। उन्होंने अपनी अद्वितीय शैली और रचनात्मक प्रस्तुति के माध्यम से छत्तीसगढ़ी रैप को नई दिशा दी।

एक ही परिवार के तीन बुजुर्गों की हत्या, दौड़ाया और धारदार हथियार से काटकर मारा

प्रयागराज। यूपी के प्रयागराज जिले में एक बार फिर सामूहिक हत्याकांड की घटना ने सनसनी फैला दी है। यमुनानगर के मेजा थाना इलाके के कुकुरकटवा गांव में एक ही परिवार के तीन बुजुर्ग सदस्यों की देर रात नृशंस हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह जब घटना का पता चला तो ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और मातम पसर गया। घटना की सूचना मिलते ही

छत्तीसगढ़ में महंगी हुई बिजली : 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोत्तरी, एक जुलाई से लागू

आयोग ने कहा- आपूर्ति लागत के कारण विद्युत टैरिफ दरों में की गई वृद्धि

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को एक बार फिर से बिजली का झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों को मंजूरी दी है। आयोग ने वितरण कंपनी के प्रस्तावित औसतन 24 फीसदी वृद्धि के मुकाबले केवल 6.23 फीसदी की औसत वृद्धि को मंजूरी दी गई। इसके कारण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 जुलाई से टैरिफ में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। वहीं बढ़ोत्तरी को लेकर आयोग का कहना है कि न केवल बिजली, कोयला, बिजली उत्पादन और आपूर्ति लागत के कारण विद्युत टैरिफ दरों में मामूली वृद्धि की गई है। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्यों की तुलना में बिजली काफी सस्ती है।



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा की गई है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। आयोग ने बिजली शुल्क में औसतन 6.23 प्रतिशत की वृद्धि की है। आयोग का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में औसतन 30 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। हालांकि उपभोग के अलग-अलग स्तर के अनुसार यह बढ़ोत्तरी 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक रहेगी। शून्य से 200 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 30 पैसे प्रति यूनिट, 201 से 600

जारी रहेगी हाफ बिजली बिल की सुविधा

सरकार की मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की खपत पर आधा बिजली बिल देने की सुविधा मिल रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर वास्तविक अतिरिक्त भार अपेक्षाकृत कम रहेगा। अनुमान है कि इन उपभोक्ताओं के बिल पर प्रभाव औसतन केवल 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट के बराबर होगा।

गैर-घरेलू श्रेणी में औसतन 20 से 40 पैसे की वृद्धि

गैर-घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में औसतन 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। वहीं कृषि पंपों के लिए दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी घोषित की गई है। हालांकि कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के कारण इस वृद्धि का सीधा प्रभाव किसानों पर नहीं होगा।

औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली शुल्क में संशोधन

उच्च दाब श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी शुल्क में संशोधन किया गया है। 220 केवी और 132 केवी श्रेणी में ऊर्जा प्रभार में 30 पैसे प्रति यूनिट व डिमांड चार्ज में 25 रुपए प्रति केवीए की वृद्धि की गई। 33 केवी में 40 पैसे और 11 केवी श्रेणी में 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी लागू होगी।

बस्तर व सरगुजा क्षेत्र के छात्रावासों को राहत

नई टैरिफ व्यवस्था में कुछ विशेष रियायतें भी दी गई हैं। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों को व्यावसायिक श्रेणी के बजाय घरेलू श्रेणी में शामिल कर राहत प्रदान की गई है। इसके अलावा विलंबित भुगतान अधिभार की व्यवस्था को भी उपभोक्ता हित में सरल बनाया गया है। अब अतिरिक्त शुल्क केवल वास्तविक विलंब अवधि के आधार पर लगेगा। घरेलू और गैर-घरेलू श्रेणी के 10 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को ऑफ-पीक अवधि में बिजली उपयोग करने पर 20 पैसे प्रति यूनिट की छूट भी मिलेगी।

पड़ोसी राज्यों से सस्ती

आयोग के अनुसार संशोधित दरों के बावजूद छत्तीसगढ़ में बिजली शुल्क पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड की तुलना में अभी भी कम है। ऐसे में राज्य में उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए बिजली दरें प्रतिस्पर्धी बनी रहेंगी। बिजली दरों में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन राहत योजनाओं, सब्सिडी और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली नीतियों के कारण आम घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम होगा।

दो माह की छुट्टियों के बाद स्कूल खुले तिलक लगाकर बच्चों का स्वागत



श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। 2 महीने की छुट्टी के बाद छत्तीसगढ़ में मंगलवार को 16 जून से स्कूल खुल चुके हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 16 जून से 27 जून तक शाला प्रवेशोत्सव मनाने की घोषणा की गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को दुर्ग भिलाई के तमाम स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया जहां बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर किताब वितरण कर उनका स्वागत किया गया। बच्चों को अनुशासित रहने

बेहतर पढ़ाई लिखाई के लिए संकल्प भी दिलाया गया। इस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने गर्मी की छुट्टियों में बढ़ोत्तरी नहीं की है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जून का महीना अपेक्षाकृत सामान्य रहा। इसके कारण 16 जून से स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया गया। हालांकि यह भी आशंका लगाई जा रही थी कि गर्मी बढ़ने के कारण स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई जाएंगी। स्कूल शिक्षामंत्री ने एक दिन पहले की कथा था कि मौसम सामान्य होने के कारण तय तारीख पर ही स्कूल खुलेंगे।

बिलासपुर में 26 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या, जांच में जुटी पुलिस

बिलासपुर। जिले के सिरागिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश नगर नयापारा में 26 वर्षीय इरफान बशीरा पिता शेख खलील की लाश मिलने से हड़कंत मच गया। पुलिस ने शव मंगलवार की सुबह बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा माना जा रहा है, लेकिन जिस तरह बीच बस्ती में युवक की बेरहमी से हत्या किया गया है, उससे दहशत फैल गई है। सीएसपी निमितेश सिंह के अनुसार एक संदेही को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है।



नीट री-एग्जाम से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला भारत में टेलीग्राम पर लगाई गई अस्थायी रोक

नई दिल्ली ए.। केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का फैसला किया है। नीट 2026 की पुनर्परीक्षा के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार द्वारा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निर्देश जारी कर भारत में टेलीग्राम की सेवाओं पर 22 जून 2026 तक अस्थायी रोक लगाने को कहा है। यह कदम 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एनटीए का मानना है कि परीक्षा से जुड़े प्रश्नपत्रों, अफवाहों, फर्जी सूचनाओं के प्रसार को रोकने में यह फैसला मददगार साबित होगा। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना उसकी सर्वोच्च



प्राथमिकता है। एनटीए के अनुसार, हाल के वर्षों में विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के दौरान सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से गलत सूचनाओं और परीक्षा सामग्री के कथित प्रसार की घटनाएं सामने आई थीं। ऐसे में एहतियाती कदम के तौर पर यह फैसला लिया गया है। पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से एनटीए ने अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत सूचना माध्यमों पर ही भरोसा करें तथा किसी भी अपुष्ट जानकारी या अफवाह से बचें।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। मृतकों के परिजनों ने पुलिस को अहम जानकारी दी है। उन्होंने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार, आरोपी ने करीब एक सप्ताह पहले परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी। यह धमकी किसी पुरानी रंजिश के चलते दी गई थी।

प्रयागराज पुलिस की टीम, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और डॉग स्कॉड के साथ मौके पर पहुंची और गहन छानबीन शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, तीनों बुजुर्गों की सोते वक्त हत्या की गई। मृतकों की पहचान अमरावती देवी पत्नी नींबूलाल (65), इंद्रावती देवी पत्नी दूधनाथ (62) और श्याम लाल पुत्र गुलजार (65) के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर

अमेरिका का बी-52 बॉम्बर उड़ान भरने के तुरंत बाद हुआ क्रैश, हादसे में आठ लोगों की मौत

एडवर्ड्स ए.। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित मोजावे रेगिस्तान में स्थित एक वायुसेना अड्डे पर बी-52 स्ट्रैटोफोर्सेस बमवर्षक विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि विमान ने एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन टेकऑफ के तुरंत बाद वह दुर्घटना का शिकार हो गया। न्यूज एजेंसी एपी ने वायु सेना के हवाले से बताया कि कैलिफोर्निया के एक सैन्य अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुए बी-52 बमवर्षक विमान में सवार आठ लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि विमान सुबह करीब 11:20 बजे एडवर्ड्स वायुसेना अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद आपातकालीन राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंच गए। लॉस एंजिलिस



के उत्तर में स्थित एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस ने सोशल मीडिया पर कहा, प्रारंभिक संकेत बताते हैं कि इस दुर्घटना में जीवित बचना संभव नहीं था। एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस अमेरिकी वायुसेना के विमान परीक्षण और विकास कार्यक्रमों का प्रमुख केंद्र है। यह लॉस एंजिलिस से लगभग 161 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।

इलाके में दिखा धुएं का गुबार

चालक दल के सदस्यों के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है, हालांकि हवाई दृश्यों में विमान का मलबा लगभग पूरी तरह नष्ट दिखाई दिया। दुर्घटनाग्रस्त के बाद वायुसेना के अड्डे के एक रनवे के निकट रेगिस्तानी क्षेत्र में आग लगने से काला धुआं उठता दिखाई दिया और आसपास कई आपातकालीन वाहन तैनात थे। सेना ने यह नहीं बताया है कि बमवर्षक विमान हथियारों से लैस था या नहीं। अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि आपातकालीन राहत कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए एयरबेस पर गैर-व्यावसायिक आगंतुकों के प्रवेश पास अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

Harsh Media

BOOK NOW!

अब हर नज़र आपके Brand पर!

- Unipole / Hoarding
- Outdoor LED Screen
- Digital LED Television
- Train Wrap Branding

- Mobile LED Vehicle
- Social media advt.
- News Paper advt.
- Branding consultancy

8253029444 | 8435918888

www.harshmediaadvertisers.com |
 info.harshmedia@gmail.com |
 [harsh_media_advertisers](https://www.instagram.com/harsh_media_advertisers)

संपादकीय

ईमानदारी की लेबलिंग

जीवन से खिलवाड़ न कर पाएँ घटिया उत्पाद

भारत में सामान्यतः उत्पादों पर गुणवत्ता व उपयोग-तिथि के दावों के बावजूद उसमें सामान के सेहत से जुड़े सरोकार सबालों के घेरे में रहे हैं। यह आम धारणा बनी हुई है कि कुछ लोग मुनाफे के लिए सामान को एक्सपाइरी डेट बर्न करने में हेरफेर करने तक से नहीं चूकते। यह भी विश्वास से नहीं कहा जा सकता है कि सामान में शामिल घटकों का विवरण ईमानदारी से लेबल पर दर्ज किया गया हो। गाहे-बगाहे मीडिया व उपभोक्ता अदालतों में ऐसे मामलों की गुंज रहती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से संवेदनशील लोगों के जीवन पर सही लेबलिंग से आंच नहीं आ सकती। इसी के मद्देनजर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएस.एस.ए.आई. द्वारा कई खाद्य कंपनियों को गुमराह करने वाले ट्रेड नाम के इस्तेमाल और सेहत से जुड़े दावों के लिए नोटिस जारी करना, निम्न ही एक स्वागतयोग्य कदम है। अक्सर प्रतिष्ठित उत्पाद वाली कंपनियों के लेबल लगाकर हल्के सामान बेचने के मामले भी उजागर होते हैं। हकीकत है कि आकर्षक पैकेजिंग के जरिये उत्पाद की न्यूट्रिशन से जुड़ी जानकारी को पार्श्व में डाल दिया जाता है। विडंबना यह है कि देश में ऐसा नियामक तंत्र विकसित नहीं हो पाया है जो लगातार जनहित में खाद्य उत्पादों की जांच-पड़ताल कर सके। निश्चित रूप से रेगुलेटरी संस्था की निगरानी सिर्फ कभी-कभार नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई कुछ समय के लिए तो सुविधाजनक है लेकिन फिर लोगों को इसकी याद दिलाई रह जाती है। इस तरह की पहल को ग्राहकों की सुरक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और जागरूकता पर आधारित लगातार चलने वाले एक राष्ट्रीय मिशन का रूप दिया जा सकता है। निश्चित रूप से लाखों भारतीयों के लिए खाने की चीजों पर लेबलिंग सेहत से जुड़ा मामला है। मसलन कशेरुक रोग से पीड़ित लोग ग्लूटेन से बचने के लिए लेबलिंग पर लिखी जानकारी पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि यह उनकी आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है।

निस्संदेह, कई एलर्जी व रोगों से जूझने वाले लोगों को कुछ उत्पादों में मौजूद पदार्थों की वजह से लंबे समय तक रहने वाली परेशानियाँ हो सकती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि उत्पादों के लेबल पर आधी-अधूरी, अस्पष्ट जानकारी ही दी जाती है। अक्सर उत्पादों पर हेल्दी, नेचुरल और आयुर्वेद पद्धति पर आधारित जैसे लुभावने शब्दों का इस्तेमाल करके ग्राहकों को भ्रमित किया जाता है, जिससे उपभोक्ता असमंजस की स्थिति में पड़ आते हैं। मधुमेह, एलर्जी और खानपान से जुड़े दूसरे परहेजों में अस्पष्ट व गलत जानकारी हानिकारक हो सकती है। उत्पादकों की ईमानदारी व उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर भरोसा करना ग्राहकों के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे-जैसे भारतीय समाज में पैकेट बंद खाद्य पदार्थों का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, देश में एक मजबूत नियामक ढांचे की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। दरअसल, देखने में आता है कि छोटे दुकानदार अपने नुकसान को बचाने के लिए उसका बोझ ग्राहकों पर डाल देते हैं। एक प्रतिबद्ध नैतिकता का अभाव इस मुनाफे के कारोबार में अक्सर नजर आता है। निस्संदेह, किसी उत्पाद के पैकेट में उल्लेखित जानकारी ग्राहक के समझने के लिए आसान होनी चाहिए।

साथ ही बिना तथ्य व तार्किकता के सेहत से जुड़े दावे करने वाले उत्पादकों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। इसके लिये जरूरी है कि समय-समय पर इन उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया की औचित्य निगरानी व पड़ताल होनी चाहिए। साथ ही बार-बार नियम तोड़ने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान भी होना जरूरी है। देश में कोशिश हो कि उपभोक्ता जागरूकता अभियान को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का हिस्सा बनाया जाए। इस अभियान में स्कूलों, हेल्थकेयर संस्थानों और विभिन्न मीडिया समूहों को आम लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए कि किसी उत्पाद में दर्ज न्यूट्रिशन लेबल को कैसे समझे। कैसे भ्रमित करने वाले दावों की पड़ताल करें। साथ ही कैसे वे सेहत के अनुकूल उत्पादों के विकल्प का चयन कर सकें। निश्चित रूप से एक जागरूक उपभोक्ता ही नैतिक मार्केटिंग के खिलाफ बचाव की राह दिखा सकता है। खाद्य उत्पाद से जुड़े कारोबारियों को कानून के बजाय नैतिक दायित्वों के निर्वहन से कारोबार में शुचिता को बनाये रखनी चाहिए।

स्वस्थ, सशक्त व स्वास्थ्य देखभाल विकास के 12 वर्ष



अनुप्रिया पटेल

बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली से आर्थिक उत्पादकता बढ़ती है, कार्यबल की संख्या में बढ़ोतरी होती है और विकास दीर्घवधि तक होता है। इसलिए, अच्छी सेहत न केवल समाज के लिए अच्छा संकेत है, बल्कि यह देश की एक संपत्ति भी है। यह वह आधार है, जिस पर मानवीय क्षमता का निर्माण होता है और देश की ताकत मापी जाती है। इसलिए, बेहतर सेहत न केवल समाज के लिए अच्छा है, बल्कि यह देश की एक संपत्ति है और इसमें लगाया गया हर रुपया देश के लोगों में किया गया निवेश है।

इस तरह, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी), यानी यह सुनिश्चित करना कि सभी लोग, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, बिना किसी आर्थिक परेशानी के, जब और जहाँ जरूरत हो, अच्छी गुणवत्ता की सभी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएँ हासिल कर सकें। यह न केवल 2030 तक हासिल किया जाने वाला सशक्त विकास का लक्ष्य है, बल्कि सेहत से जुड़ी एक प्राथमिकता भी है।

भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 (एनएचपी 2017), सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) और एसडीजी 3 को हासिल करने के लक्ष्य के अनुरूप है और यह एक सरल लेकिन मजबूत सोच पर आधारित है स्वास्थ्य सेवाओं तक हर व्यक्ति की पहुँच होनी चाहिए। इसके चार स्तंभ, किफायती होना, पहुँच, गुणवत्ता और उपलब्धता, उस सोच को वास्तविकता में बदलते हैं और जीवन के सभी चरणों में देखभाल को एक व्यापक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। लक्ष्यों के अनुरूप, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्यों को स्वास्थ्य प्रणाली का एक एकीकृत तीन-स्तरीय मॉडल प्रदान करने में मदद करता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी इलाकों (कमजोर वर्गों सहित) के बीच दोतरफा

रेफरल लिंक शामिल हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) प्राथमिक स्तर पर बीमारी से बचाव, सेहत को बढ़ावा देने, इलाज, पुनर्वास और प्रशामक देखभाल जैसी व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ देते हैं। ईसजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म इन एएएम के जरिए समुदाय को विशेषज्ञों से जोड़कर विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। साथ ही, एक खास टेली-मानस प्लेटफॉर्म भी है, जिसने अब तक कुल 38.93 लाख लोगों तक पहुँच बनाई है।

एएएम से जुड़े द्वितीय स्तर के केंद्र जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), प्रथम रेफरल इकाई (एफआरयू) और जिला अस्पताल (डीएच) होते हैं, जो विशेषज्ञ के समक्ष इलाज और अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा के लिए रेफरल का पहला ज़रिया होते हैं। वहीं, मेडिकल कॉलेज जैसे तृतीयक संस्थान सबसे ऊपर होते हैं और ज्यदा जटिल व सुपर-स्पेशलिस्ट सेवाओं की जरूरतें पूरी करते हैं।

इस तीन-स्तरीय प्रणाली को सरकारी स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी का समर्थन प्राप्त है। पिछले दशक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर होने वाला खर्च 168% बढ़ गया है, जो स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानने के संकेत के संकेत को दर्शाता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का सफर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के विस्तार और प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही से समरथा होने से पहले ही ध्यान रखने वाली देखभाल की ओर ज़रूरी बदलाव को दिखाता है। व्यापक स्वास्थ्य पैकेजों का संख्या 6 से बढ़ाकर 12 करना, भारत की बदलती आबादी और बीमारियों के बदलते पैटर्न के हिसाब से उठाया गया एक ज़रूरी कदम है। बढ़ती उम्र की आबादी और गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के बढ़ते मामलों आधारित है स्वास्थ्य सेवाओं तक हर व्यक्ति की पहुँच होनी चाहिए। इसके चार स्तंभ, किफायती होना, पहुँच, गुणवत्ता और उपलब्धता, उस सोच को वास्तविकता में बदलते हैं और जीवन के सभी चरणों में देखभाल को एक व्यापक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। लक्ष्यों के अनुरूप, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्यों को स्वास्थ्य प्रणाली का एक एकीकृत तीन-स्तरीय मॉडल प्रदान करने में मदद करता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी इलाकों (कमजोर वर्गों सहित) के बीच दोतरफा



लोगों को उनके घर के पास स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें। इस विस्तार का असर एएएम में 120 करोड़ से ज्यादा ओपीडी परामर्श, 70 करोड़ से ज्यादा ईसजीवनी टेली-परामर्श और अच्छी सेहत व कल्याण को बढ़ावा देने वाले 46.1 करोड़ से ज्यादा वेलनेस सत्रों में साफ़ दिखाता है। प्राथमिक देखभाल स्तर पर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और आम कैंसर (जैसे ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर) के लिए आबादी-आधारित स्क्रीनिंग 30 साल से ज्यादा उम्र के सभी व्यक्तियों के लिए की जाती है, जिससे बीमारी का जल्दी पता लगाना एक सामान्य प्रक्रिया बन जाती है। यह जांच 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' के तहत सेवा वितरण का एक अहम हिस्सा है, जो एनसीडी की रोकथाम को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में शामिल करती है। एनसीडी सेवाओं का विस्तार बीमारी का जल्दी पता लगाने, रोकथाम, प्रबंधन और इलाज के लिए एक बहु-स्तरीय प्रयास है। समर्पित एनसीडी क्लीनिक, डे-केयर कैंसर केंद्र, तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्र और राज्य कैंसर संस्थान, उन्नत ऑन्कोलॉजी सेवाओं को विकेंद्रीकृत करते हैं और विशेषज्ञ देखभाल को मरीज के करीब लाते हैं।

साथ ही, बचाव से जुड़ी गतिविधियों के लिए 'होल-ऑफ-गवर्नमेंट' दृष्टिकोण अपनाया जाता है। एफएसएसएआई स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देता है, 'फिट इंडिया मूवमेंट' शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और आयु, मंजवाली योग और कल्याण को आगे बढ़ाता है। लगातार चलने वाले जन-जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य दिवस मानने जैसे कार्यक्रम इन प्रयासों को और मजबूत करते हैं। खाने के तेल की खपत

को 10% कम करने की प्रधानमंत्री मोदी की निजी अपील एक सरल लेकिन दमदार सोच को जाहिर करती है कि एनसीडी के खिलाफ लड़ाई अस्पतालों के साथ-साथ घरों में भी जीती जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार के लिए, एएएम स्तर पर 'सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर्स' का एक नया कैडर शुरू किया गया, जिससे क्लिनिकल और जन स्वास्थ्य से जुड़ी विशेषज्ञता समुदायों के ओर करीब आ गई। यह विस्तार लोगों के घर-द्वार तक भी पहुँचा, जहाँ फ्रंटलाइन नेटवर्क बढ़कर 10 लाख से ज्यादा आशा (आशा) कार्यकर्ताओं तक पहुँच गया, जिन्होंने समुदाय को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ा।

विस्तार के साथ-साथ, भारत ने देखभाल के मापदंडों को बदलने की ज्यदा मुश्किल चुनौती भी स्वीकार की। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, जो देश में ही विकसित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणिकृत हैं, ने गुणवत्ता को सिर्फ एक इच्छा से बदलकर एक जवाबदेही बना दिया। 65,000 से ज्यादा जन स्वास्थ्य केंद्र, जिनमें 54,926 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शामिल हैं, अब एनक्यूएस द्वारा प्रमाणिकृत हैं। इसके अलावा, आईपीएचएल के लिए लैब मानकों ने व्यवस्था में और मजबूती और सटीकता लाई है।

एनक्यूएस की सफलता का राज सिर्फ मानदंड नहीं, बल्कि उसके आस-पास बनी व्यवस्था था, जैसे माँ और नवजात शिशु की देखभाल के लिए 'लक्ष्य', साफ-सफाई और संक्रमण नियंत्रण के लिए 'क्याकल्प' और बच्चों की सेहत के लिए 'मुस्कान'। इन सभी ने मिलकर गुणवत्ता को सिर्फ एक मानक के बजाय एक आधारभूत स्तर बना दिया है। नतीजा

यह है कि अब ऐसी व्यवस्था तैयार हुई है, जिसमें न सिर्फ ज्यदा लोगों का इलाज होता है, बल्कि बेहतर इलाज भी किया जाता है।

अगर प्राथमिक देखभाल व्यवस्था का पहला वादा है, तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन और 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम जैसे खास कार्यक्रम देश भर में ओओपीडी को कम करने के संस्कार के संकेत को और दिखाते हैं। इससे उन परिवारों की कुल मिलाकर 10,102 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत हुई है, जिन्हें वरना यह बोझ अकेले उठाना पड़ता।

लोगों की सेहत की जिम्मेदारी लोगों को ही सौंपते हुए, भारत ने अपने सामुदायिक मंचों को मजबूत किया है। यह एक सोच-समझकर बनाया गया, विकेंद्रीकृत ढांचा है, जो योजनाकृत, निगरानी और जवाबदेही को स्थानीय लोगों के हाथों में सौंपता है। विलेज हेल्थ, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटीज (वीएचएसएसी), जन आरोग्य समितियाँ (जेएसए) और रोगी कल्याण समितियाँ (आरकेएस) ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय भागीदार बनाया है। शहरी इलाकों में, महिला आरोग्य समितियाँ (एमएसए) पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसेमंद प्रतिक्रिया के लिए समुदाय की आवाज़ को अहमियत देते हुए, महिलाओं को सामुदायिक आउटररी के केंद्र में रखकर इस फोकस को और गहरा करती हैं।

वास्तविक स्वास्थ्य सुरक्षा का अर्थ है आज के खतरों के लिए भी तैयार रहना। 2021 में 64,180 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू की गई पीएम-एबीएचआईएम योजना सीधे तौर पर कोविड-19 से मिले सबक पर आधारित है, जैसे कि अचानक बढ़ने वाली ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता बनाना, लेबोरेटरी नेटवर्क को मजबूत करना, बीमारियों की वास्तविक समय में निगरानी का दायरा बढ़ाना और 'वन हेल्थ' शोध ढांचा विकसित करना। असल में, यह मुश्किल समय से मिले सबक को एक मजबूत जन स्वास्थ्य प्रणाली में बदलने का काम है।

(लेखक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री हैं)

महिला सुरक्षा, जवाबदेही और न्याय के सवाल



ही स्थानांतरित किया गया। बाद में मामले में कथित रूप से जांच प्रक्रिया और बयान दर्ज होने के आधार पर ब्लोजर रिपोर्ट तैयार होने की बात कही गई। इसके अलावा वर्ष 2017 में भी एक दलित महिला द्वारा अस्पताल परिसर में दुर्घटना का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने और मामला अदालत तक पहुँचाने की बात सामने आई। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौते की स्थिति बनने की बात सामने आई।

वर्तमान घटनाक्रम में राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन 6 जून को कुरुक्षेत्र पहुँचीं और पूरे मामले की समीक्षा की। सभी जानते हैं कि नर्सों का कार्य डॉक्टरों की निगरानी करना नहीं, बल्कि मरीजों की

अभियान यौन हिंसा के आरोपी और उनके समर्थकों को बचाने की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जनवादी महिला समिति के नेतृत्व में 5 जून को कुरुक्षेत्र में एक बड़ा निरोध प्रदर्शन किया गया। महिला नेतृत्व अस्पताल में पीड़ित बच्ची से भी मिला। उसके बाद ही राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अगले दिन कुरुक्षेत्र पहुँचीं। वहाँ उनके व्यवहार को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आईं, जिन्हें आयोग की गरिमा के अनुरूप नहीं माना गया। आरोप है कि उन्होंने आरोपी के बजाय नर्सिंग स्टाफ पर ही दोष मढ़ने की कोशिश की। सवाल यह है कि चिकित्सक के रूप में कार्यरत उस व्यक्ति पर पहले भी ऐसे गुंडी आरोप लगाते रहे हैं, फिर भी सेवानिवृत्ति के बाद उसे दोबारा नियुक्ति किसकी है? यह प्रश्न प्रशासनिक और नैतिक प्रक्रिया की जवाबदेही की ओर संकेत करता है। यह आशंका भी जताई जा रही है कि उच्च स्तर पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संरक्षण से वह कानून की सख्ती से बचता रहा। ऐसे गंभीर आरोपों के बावजूद उसके खिलाफ प्रभावी दंडात्मक कदम नहीं उठाए गए।

महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के

गठित संवैधानिक आयोग की अध्यक्ष होने के बावजूद, यदि सार्वजनिक रूप से नर्सिंग कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार और भाषा के प्रयोग के आरोप सामने आते हैं, तो इसे गंभीर आपत्ति के रूप में देखा जाता है। ऐसे मामलों में अपेक्षा की जाती है कि वे अस्पताल के प्रशासनिक कार्यालय में बैठकर औपचारिक तरीके से जानकारी प्राप्त करतीं। साथ ही सरकार से सवाल उठातीं कि संबंधित डॉक्टर की पुनर्नियुक्ति कैसे हुई। पूरे प्रकरण को लेकर चर्चा होती रही है कि कहीं यह प्रभावशाली राजनीतिक संरचना से जुड़े दबावों का परिणाम तो नहीं है। विभिन्न मामलों से जुड़े प्रकरण या कुरुक्षेत्र अस्पताल में 15 वर्षीय दलित लड़की के कथित यौन शोषण ने यह सवाल और गंभीर कर दिया है कि क्या आरोपियों को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संरक्षण मिलता रहा है। ऐसी घटनाओं का सामाजिक माहौल और सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है। सरकार से अपेक्षा है कि दोगी डॉक्टर की पुनर्नियुक्ति को उच्चस्तरीय-निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

लेखिका महिला अध्ययन केंद्र एमडीयू, रोहतक की निदेशक रही हैं।

एफटीए विकसित भारत के लिए नई व्यापार संरचना का निर्माण कर रहे हैं



राजेश अग्रवाल

'विकसित भारत' का विजन हासिल करने के लिए अगले दो दशकों तक आर्थिक विकास की उच्च दर बनाए रखना जरूरी है। भारत का विशाल घरेलू बाजार इस विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इंजन है, लेकिन केवल इसी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। वैश्विक प्रतिस्पर्धी पैमाने और वास्तविक तकनीकी परिवर्तन हासिल करने के लिए, भारत मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के नेटवर्क के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मजबूती से एकीकृत हो रहा है। जहाँ डब्ल्यूटीओ समझौते नियम-आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए आधारशिला प्रदान करते हैं, वहीं एफटीए इच्छुक साझेदारों को डब्ल्यूटीओ आधारशिला पर आगे बढ़ाते हुए रुचि के अन्य क्षेत्रों में अधिक गहराई से एकीकरण करने में सक्षम बनाते हैं।

आर्थिक एकीकरण और साझेदार देशों के अनुसार नियम बनाने के महत्वपूर्ण चालक के रूप में वर्तमान में लगू 384 अधिसूचित एफटीए अपनी उपयोगिता रेखांकित करते हैं। ये एफटीए महत्वपूर्ण बाजार तक पहुंच बनाते हैं और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के अनिश्चित हालात से बचाने

के लिए संस्थागत रूपरेखा (व्यूप्रिंट) हैं। वैश्विक आर्थिक अवसरों तक पहुंच भी उन भारतीय व्यवसायों के लिए जरूरी है, जो बड़े पैमाने पर काम करके वैश्विक चैंपियन के तौर पर उभरना चाहते हैं। लेकिन फायदा केवल बड़े व्यवसायों तक सीमित नहीं है। एफटीए स्टार्ट-अप, एमएसएमई, किसानों, मछुआरों और भारतीय प्रतिभा के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर के द्वार खोलते हैं, जो अपनी क्षमताओं का विश्व स्तर पर लाभ उठाना चाहते हैं। ये बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ टैरिफ, सेवा बाजार तक पहुंच और पारदर्शी व्यापार नियमों को शामिल करती हैं, जिससे भारतीय व्यवसायों को लंबी अवधि के निवेश के लिए भरोसेमंद वातावरण मिलता है।

भारत की व्यापार बातचीत की रणनीति काफी विकसित हो चुकी है, और इसका ध्यान उन पूरक अर्थव्यवस्थाओं पर है, जो वस्तु और सेवाओं के लिए मुख्य निर्यात बाजार के रूप में काम करती हैं। हाल के मुक्त व्यापार समझौतों का एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में समान अवसर प्राप्त हों। यह समानता विशेष रूप से वस्त्र, परिधान और जूते जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए जरूरी है, जहाँ ऐतिहासिक रूप से भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगातार रहे हैं, जबकि प्रतिस्पर्धियों को शून्य मुक्त पहुंच मिलती है। कनाडा, इज़राइल और ईएफटीए और एमईआरसीओएसयूआर जैसे समूहों के साथ भी भारत

व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सेवाएँ भारत की निर्यात रणनीति और इसके एफटीए वार्ताओं के केंद्र में हैं। सीमापार डिजिटल डिलीवरी पर पकड़े वादे करके, हाल के एफटीए, तेजी से बढ़ते वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) इकोसिस्टम, तकनीकी स्टार्टअप और डिजिटल नवोन्मेषियों के बीच निवेशकों के भरोसे को बढ़ाने में मदद करते हैं।

डिजिटल डिलीवरी सेवाओं के अलावा, एफटीए ने भारत को वार्ताओं में नए तरीके अपनाने का मौका दिया है, जिससे ऐसी बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ हासिल हुई हैं, जो भारतीय प्रतिभा, खासकर युवाओं के आवागमन को बढ़ाती हैं। मुख्य उपलब्धियों में शामिल हैं - छत्र और पेशेवरों के लिए आवागमन प्रावधान और साइड-लेटर, भारत-यूके दोहरा योगदान समझौता (डीसीसी) जैसे फ्रैन्चवाइज, जो अस्थायी कार्य के लिए दोहरी सामाजिक सुरक्षा कवरेज को रोकते हैं, और योग जैसे खास क्षेत्रों में आवागमन अधिकार।

भारत के नई पीढ़ी के एफटीए की एक विशेषता व्यापार और निवेश के बीच गहरे संबंध को मान्यता देना है। प्रमुख वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करके और पेशेवरों के लिए आवागमन प्रावधान और साइड-लेटर, नेटवर्क बढ़ती मांग के साथ मिलकर भारत को निर्माण और निवेश के लिए बेहद आकर्षक गंतव्य बनाता है।

हाल के समझौते और आगे बढ़ते हुए बाजार तक पहुंच को निवेश परिणामों से सीधे जोड़ते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है, भारत-ईएफटीए समझौता, जिसमें

यह शर्त रखी गयी है कि ईएफटीए देशों को भारतीय बाजार तक पहुंच तभी मिलेगी, जब वे 100 बिलियन डॉलर के एफडीआई का वादा करेंगे और भारत में दस लाख नौकरियाँ पैदा करेंगे। भारत-यूजीएलईए एफटीए में भी ऐसे ही प्रावधान हैं, जिनके तहत लंबे समय के निवेश के वादे के बदले भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार तक पहुंच की सुविधा दी गयी है। आधुनिक व्यापार अब केवल टैरिफ तक सीमित नहीं है; इसके लिए 21वीं सदी के आयामों को समझना और नियमों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे व्यापार में तकनीकी बाधाएँ (टीबीटी), स्वच्छता और पादप-स्वच्छता से जुड़े उपाय (एसपीएस), और व्यापार सुगमता (टीएफ)। भारत के अगली पीढ़ी के एफटीए इन रूपरेखाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।

अक्सर, टैरिफ की तुलना में उत्पाद मानक और अन्य नियामक आवश्यकताएँ बाजार तक पहुँचने में ज्यदा बड़ी रुकावट पैदा करती हैं। भारत के एफटीए में नियामक समन्वय और सहयोग के प्रावधान भारतीय निर्यातकों के संदर्भ में इन बाधाओं को कम करने के लिए व्यवस्थित व संस्थागत तरीके प्रदान करते हैं।

पर्यावरण और श्रम मानक व्यापार में संभावित बाधाओं के रूप में उभर रहे हैं और इनके लिए उपाय न करना अब कोई विकल्प नहीं है। भारत के नए एफटीए इन चिंताओं को दूर करने के लिए ऐसी सहयोगात्मक व्यवस्था पेश करते हैं, जिससे भारतीय हितों को नुकसान न पहुंचे। ये वैश्विक साझेदारों को भरोसा दिलाते हैं कि भारत मानकों

के मामले में सबसे निचले स्तर पर पहुँचने की होड़ से बचते हुए, वास्तविक नवाचार और बड़े पैमाने पर काम करके प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करना चाहता है।

भारत की एफटीए नीति टुकड़ों में नहीं है, या देश-दर-देश नहीं है। यह जानबूझकर ऐसी पूरक अर्थव्यवस्थाओं को लक्षित करती है, जिनकी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में दो-तिहाई और वैश्विक आयात मांग में 75% की हिस्सेदारी है। सबसे जरूरी बात यह है कि इन एफटीए पर बातचीत हितधारकों की निरंतर भागीदारी और संपूर्ण सरकार दृष्टि पर निर्भर करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि व्यापार नीति भारत के औद्योगिक विकास, नवाचार और सामाजिक-आर्थिक प्रगति जैसी व्यापक प्राथमिकताओं के अनुरूप है और समझौते इस तरह से बनाए जाएँ कि संवेदनशील क्षेत्र और आबादी सुरक्षित रहें।

खास तौर पर, एफटीए में ऐसे मजबूत प्रावधान शामिल किये जाते हैं, जिनसे यह सुनिश्चित होता है कि भारतीय बाजार को खोलने से घरेलू हितधारकों को नुकसान नहीं होगा। संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में उदारीकरण लंबे समय में धीरे-धीरे किया जाता है, ताकि स्थानीय उद्योगों को तालमेल बिटाने का समय मिल सके। कृषि जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों को एमएसएमई और किसानों की सुरक्षा के लिए बाहर रखा गया है, साथ ही अचानक आयात बढ़ने की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा उपाय भी मौजूद हैं।

(लेखक वाणिज्य मंत्रालय के सचिव हैं।)

खास-खबर

किसानों को खाद-बीज समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश

रायपुर। खरीफ सीजन 2026 के महेनजर कृषि विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। संयुक्त संचालक कृषि ने बेमेतरा जिले के कृषि अधिकारियों को बैटक लेकर बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता सहित विभिन्न तैयारियों की समीक्षा की। संयुक्त संचालक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त खाद-बीज उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने खरीफ फसलों के रकबा विस्तार, उन्नत कृषि तकनीकों के प्रचार-प्रसार तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों के किसानों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने, मौसम आधारित कृषि सलाह उपलब्ध कराने और कृषि संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक पहुंचे और आधुनिक खेती पद्धतियों के प्रति किसानों को लगातार जागरूक किया जाए।

महिला उद्यमियों को मिला बाजार विस्तार का मंत्र

रायपुर। बदलते तकनीकी दौर में महिला उद्यमियों को आधुनिक साधनों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महेनजर-चिरमिरी-भरतपुर जिले में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। नवा बिहान क्लस्टर में आयोजित डिजिटल साक्षरता कार्यशाला ने महिलाओं को ऑनलाइन विपणन, ब्रांड निर्माण और इंटरनेट आधारित व्यापार की नई संभावनाओं से परिचित कराया गया। कार्यशाला का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और महिला संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को आधुनिक विपणन तकनीकों की जानकारी देकर उनके उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाना था। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को उत्पाद पहचान निर्माण, आकर्षक पैकेजिंग, लेबलिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, ऑनलाइन विक्रय मंचों तथा बाजार से जुड़ने के विभिन्न तरीकों की व्यवहारिक जानकारी दी।

गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य से सुदृढ़ हुआ राजस्व प्रशासन

रायपुर। कोरबा जिले में राजस्व प्रशासन को अधिक सक्षम एवं जनोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत नवीन तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, कोरबा द्वारा निर्मित इन आधुनिक भवनों में अधिकांश स्थानों पर नियमित कार्यालयीन कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, जिससे प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पर्यावरण एवं अधोसंरचना मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोरबा जिले के लिए 5 नवीन तहसील कार्यालय भवन तथा 1 अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कुल 4 करोड़ 3 लाख 63 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस स्वीकृति के अंतर्गत भैंसमा, बरपाली, दीपका, पसान एवं अजागरबहार में नवीन तहसील कार्यालय भवन तथा पाली में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया है। वर्तमान में भैंसमा, बरपाली, दीपका, पसान तथा पाली स्थित नवीन भवनों में नियमित रूप से कार्यालयीन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण प्राप्त हुआ है।

निष्क्रिय सिंचाई योजना को मिला नया जीवन, गुतकिया के किसानों को मिलेगी वर्षभर सिंचाई सुविधा

लगभग 12 लाख रुपए की लागत से नहर मरम्मत कार्य पूर्ण, 100 एकड़ कृषि भूमि होगी सिंचित, खरीफ और रबी दोनों फसलों को मिलेगा लाभ

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में कृषि अधोसंरचना को मजबूत करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जशपुर जिले के मनोरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पण्डरसिली के आश्रित ग्राम गुतकिया में वर्षों से निष्क्रिय पड़ी सिंचाई योजना को पुनर्जीवित कर किसानों के लिए उपयोगी बनाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की भावना के अनुरूप सिंचित क्षेत्र के विस्तार तथा पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के पुनरोद्धार के लिए जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई। इसके तहत गुतकिया व्यपवर्तन योजना की नहर मरम्मत का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।

मनरेगा से मिली नई गति

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत इस कार्य के लिए 11 लाख 98

जैविक खेती से बढ़ेगी किसानों की आय, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बल: मंत्री केदार कश्यप

किसानों को जैविक खेती की उन्नत तकनीकों से जोड़ने कृषि कार्यशाला का आयोजन, दंतेवाड़ा को जैविक कृषि का मॉडल जिला बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। किसानों और कृषि प्रेमियों को रासायनिक खादों व कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक और टिकाऊ खेती करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु आयोजित की गई है। दंतेवाड़ा जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय जैविक कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसानों, ग्रामीण युवाओं, महिला स्व-सहायता समूहों और कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। यहां की प्राकृतिक परिस्थितियां और किसानों की मेहनत जैविक कृषि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती केवल उत्पादन बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य,



पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से भी जुड़ी है। जैविक खेती अपनाकर किसान भूमि को उर्वरता बनाए रखने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्यान्न उत्पादन कर सकते हैं।

वन मंत्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य

सरकार भी किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और कृषि विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने किसानों से खेतों की मेड़ों पर अधिक से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे भूमि संरक्षण, जल संवर्धन और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिलेगा।

क्षेत्रीय विधायक चौतराम अटामी ने कहा कि जिले के किसान जैविक एवं प्राकृतिक खेती को अपनाकर बेहतर उत्पादन और अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र

वैज्ञानिकों ने दी उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी

कार्यशाला के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने जैविक खेती, हरी खाद, जैव उर्वरक, वर्मी कम्पोस्ट, प्राकृतिक कीट एवं रोग प्रबंधन, मूल्य संवर्धन तथा जैविक उत्पादों के विपणन से संबंधित महत्वापूर्ण जानकारी किसानों को दी। किसानों की समस्याओं का समाधान भी विशेषज्ञों द्वारा किया गया।

विभिन्न विभागों ने लगाए जानकारी एवं प्रदर्शनी स्टॉल

कार्यक्रम में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग तथा भूमगादी संस्था द्वारा स्टॉल लगाकर किसानों को विभिन्न योजनाओं, तकनीकों और कृषि नवाचारों की जानकारी दी गई। साथ ही कृषकों को कृषि आदान सामग्री एवं आम के पौधों का वितरण भी किया गया।

किसानों को वैज्ञानिक जानकारी, प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराकर खेती को अधिक उन्नत एवं लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने किसानों से कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों द्वारा रागी से तैयार केक का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि ने केक काटकर महिला समूहों के

प्रयासों की सराहना की और मूल्य संवर्धन आधारित गतिविधियों को ग्रामीण आजीविका का महत्वपूर्ण माध्यम बताया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविन्द कुंजाम, जनपद पंचायत अध्यक्ष सुनीता भास्कर सहित जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी तथा जिले के विभिन्न गांवों से आए किसान, ग्रामीण युवा और महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्यएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं।

मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर फोकस : गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रशासन सख्त

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में बेमेतरा जिले में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

सीएमएचओ कार्यालय में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में डॉ. रोहेलेडर ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता केवल योजनाओं के संचालन से नहीं, बल्कि उनके जमीनी प्रभाव से तय होगी। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच, हाई रिस्क प्रेनैसी की पहचान और निष्क्रिय निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए



शुन्य होम डिलीवरी के लक्ष्य की दिशा में गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में नियमित टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, वित्तीय प्रबंधन और ऑनलाइन स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणालियों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक गर्भवती महिला का जन्मी पोर्टल पर पंजीयन, बच्चों का यू-विन पोर्टल पर रिकॉर्ड और टीबी मरीजों की जानकारी

निष्क्रिय पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से दर्ज की जाए। डॉ. रोहेलेडर ने कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं में डेटा की शुद्धता और पारदर्शिता बेहतर परिणामों की आधारशिला है।

मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रत्येक मृत्यु प्रकरण की गहन समीक्षा, कारणों का विश्लेषण और सुधारात्मक उपायों को प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

एसएनसीयू, एनबीएसयू और एचडीयू जैसी विशेष इकाइयों को कार्यक्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में सचन कृष्ण खोड अभियान, पल्स पोलियो अभियान और टीबी मुक्त पंचायत अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों को माइक्रोप्लानिंग मजबूत करने, फ़ैल्ड टीमों को प्रशिक्षित करने तथा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

डॉ. रोहेलेडर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य केवल उपचार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। इसके लिए फ़ैल्ड विजिट बढ़ाने, रेफरल व्यवस्था को मजबूत करने और तकनीकी आधारित निगरानी तंत्र को प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

नदियों के पुनरुद्धार एवं पुनर्जीवित करने संबंधी राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित राज्य की प्रमुख नदियों के पुनरुद्धार एवं पुनर्जीवित करने गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक यहां मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में प्रवाहित हो रही नदियों के पुनर्जीवन हेतु किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

नदियों का संरक्षण से जन स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में बैठक में जिलों के कलेक्टरों से नदियों के कैचमेंट एरिया में बनायी गई विविध जल संरक्षण एवं संचयन की कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा है कि हाईकोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार नदियों के



पुनर्जीवित एवं पुनरुद्धार के कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों से नदियों के कैचमेंट एरिया में ऐसे जनउपयोगी कार्यों को लिया जाए जो भविष्य में नदियों के आस-पास रहने वाले लोगों की जरूरतों के अनुरूप हो। मुख्य सचिव ने नदियों के कैचमेंट एरिया में किए जाने वाले कार्यों से स्थानीय सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से जोड़ने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा है कि जिले से उद्गम होने

वाली नदियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी रखी जाए। जिससे नदियों के बारे में छात्रों को जानकारी मिले। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं का भ्रमण नदियों के उद्गम स्थल पर कराया जाए और नदियों की जानकारी के संबंध में छात्रों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। कलेक्टर ने नदियों के उद्गम स्थलों पर मेला उत्सव जैसे आयोजनों को करने के लिए भी कहा। बैठक में कलेक्टर रायगढ़, कोरबा, गोरिला-पेण्ड्रा-मरवाही, सरगुजा, कोरिया, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, गरियाबंद और धमतरी के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिले में स्थित नदियों की वास्तविक स्थिति और संचालित कार्ययोजनाओं एवं परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टरों को नदियों के संरक्षण, संवर्धन के लिए जिला स्तरीय समितियों के संबंध में जानकारी दी।

वनोपज आधारित आजीविका को मिल रही नई पहचान: रुपसाय सलाम

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रुपसाय सलाम ने जशपुर जिले के वन धन विकास केंद्र पनचक्की का निरीक्षण कर वहां संचालित वनोपज आधारित गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र में लघु वनोपजों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन कार्यों का अवलोकन करते हुए केंद्र की उपलब्धियों की सराहना की।

निरीक्षण के दौरान सलाम ने केंद्र में निर्मित आसुर्वेदिक उत्पादों, विशेष रूप से आरोग्य अमृत अवलेह एवं चसाअवलेह के निर्माण, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि वन धन विकास केंद्र स्थानीय वन संसाधनों को आर्थिक अवसरों में बदलने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।

उन्होंने केंद्र द्वारा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि लघु वनोपजों का वैज्ञानिक प्रसंस्करण एवं मूल्य



संवर्धन ग्रामीण और वनान्चल क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

श्री सलाम ने वनोपज आधारित उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता तथा बाजार में उपलब्धता को और बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को उनके पारंपरिक संसाधनों का अधिकतम लाभ मिले और उनकी आजीविका मजबूत हो।

उद्योग मंत्री देवांगन ने जलप्रदाय योजना विस्तार कार्य का किया भूमिपूजन

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर संजुदेवी राजपूत ने आज नगर पालिक निगम कोरबा के पौने 37 करोड़ रूपये की लागत वाले जलप्रदाय योजना विस्तार कार्य का भूमिपूजन किया, इस कार्य के पूर्ण हो जाने के पश्चात निगम क्षेत्र की ऐसे बस्तियों जहाँ पानी की किल्लत थी, वह समस्या अब दूर होगी तथा समस्योजनित बस्तियों, पारों एवं मोहल्लों में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा जिला खनिज न्यास मद (डीएमएफ) से 36 करोड़ 73 लाख रूपये की लागत से जलप्रदाय योजना का विस्तार कार्य किया जाना है, इसके अंतर्गत 20 एमएलडी के जलउपचार संयंत्र के



साथ-साथ इमलीडुंगू में 12 लाख 60 हजार लीटर की क्षमता वाली पानी टंकी, दादरखुर्द में 22 लाख 50 हजार लीटर की क्षमता वाली पानी टंकी एवं रुमगरा में 10 लाख 80 हजार लीटर की क्षमता वाली पानी टंकी यानी उच्च स्तरीय जलागार का निर्माण किया जाएगा, वहीं 15.3 किलोमीटर पाईप लाईन भी बिछाई जाएगी। योजना के पूर्ण होने पर इमलीडुंगू मोतीसागरपारा, भिलाईखुर्द, बरबसपुर, करनाला, मानिकपुर, रुमगरा, देलवाडीह, खरमोरा, दादरखुर्द, बेलगिरी बस्ती में निवासरत नागरिकों को पेयजल

संजुदेवी राजपूत के हाथों सम्पन्न किया गया।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हम सबको जिला खनिज न्यास मद के रूप में एक बड़ी सौगात दी है, जिसके परिणाम स्वरूप जिलों में अरबों रूपये के विकास कार्य इस मद के अंतर्गत हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि आज जिस महत्वपूर्ण पेयजल योजना विस्तार कार्य का शुभारंभ किया गया है, वह भी जिला खनिज न्यास मद से स्वीकृत हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि हर व्यक्ति के पास पक्का मकान हो, हर घर में बिजली की सुविधा व शौचालय हो, हर घर तक पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो, और इन्ही सब का परिणाम है कि आज इस दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य हो रहे हैं।

आज इमलीडुंगू गोमाता चौक में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान इस महत्वपूर्ण विकास कार्य का भूमिपूजन उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन व महापौर

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी

पहले बाद में
JITUZ CUT N SHINE
93009-11331

रंगोली वैग्लस के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रॉनिक के बाजू में इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्गा (उ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z3
PR. 0748-4060131

अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता

लिंग रोड, केम्प 2, पावर हाउस, भिलाई
फोन: 09826389666, 8839749539

‘अपने अंदर के बच्चे को कभी मत मरने दो’

रश्मिका मंदाना ने बताया ग्लो का सीक्रेट

रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘कांकेटल 2’ को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच वह इंस्टाग्राम पर लाइव आई और उन्होंने अपने फैन से बातचीत की। उन्होंने एक फैन से बताया कि उनकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है। आइए जानते हैं दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है?

इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन के दौरान रश्मिका के एक फैन ने उनसे उनकी ग्लोइंग स्किन का राज पूछा। इसके जवाब में रश्मिका ने प्रोडक्ट या वेलनेस ट्रेड्स की सलाह देने के बजाय एक दिल को छू लेने वाला जवाब दिया। जिसे

सुनकर फैस ने उनकी काफी तारीफ की।

रश्मिका ने दी ये सलाह

रश्मिका ने कहा ‘ऐसे लोगों के साथ रहो, जो तुम्हारे भीतर के बच्चे को जिंदा रखें। जो अपने भीतर के बच्चे को भी खुश और सुरक्षित रखें। जब तुम दोनों अपने इस मासूम हिस्से की रक्षा करोगे, तब तुम सच में खुश रहोगे।’ उनका मतलब था कि खुश और पॉजिटिव रहने ने स्किन ग्लो करती है।

किस काम से मिली सबसे ज्यादा खुशी?

इसी सेशन के दौरान एक यूजर ने उनकी शादी और जिंदगी से जुड़ा

सवाल पूछा। फैन को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सपना सच हो गया हो। एक दूसरे फैन ने उनसे पूछा कि रश्मिका ने अपने जीवन में सबसे खुशी वाला मौन सा काम किया है? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा ‘मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी की है।’

वर्कफ्रंट

रश्मिका के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उनकी फिल्म ‘कुबेर’ रिलीज हुई। इसमें उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। वह जल्द ही ‘कांकेटल 2’, ‘मायसा’, ‘एनिमल पार्क’, ‘पुष्पा 3’ जैसी फिल्मों का हिस्सा होंगी।

वेदांग रैना की नई फिल्म में आया बड़ा मोड़, नाओमिका सरन के साथ प्रगति श्रीवास्तव भी निभाएंगी अहम रोल

बॉलीवुड में इन दिनों नई जोड़ियों और नई कहानियों को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच अभिनेता वेदांग रैना की आने वाली फिल्म को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। अब तक चर्चा थी कि इस फिल्म में वेदांग के साथ नाओमिका सरन नजर आएंगी, लेकिन अब खबर है कि फिल्म में एक और अभिनेत्री प्रगति श्रीवास्तव की भी एंट्री हो गई है।

बताया जा रहा है कि यह फिल्म रोमांस, कॉमेडी और रहस्य से भरपूर होगी और इसकी कहानी में दोनों अभिनेत्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जानकारी के मुताबिक, फिल्म का नाम अभी तय नहीं किया गया है। फिल्म का निर्माण मैडॉक फिल्म्स कर रहा है। वहीं निर्देशन की जिम्मेदारी जगदीप सिद्धू पर हैं। फिल्म की कहानी को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसमें एक दिलचस्प प्रेम कहानी देखने को मिलेगी, जिसमें कई रोमांचक मोड़ होंगे।

फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया, प्रगति श्रीवास्तव का किरदार फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बताया जा

रहा है कि फिल्म में वेदांग रैना के किरदार की जिंदगी में दो अलग-अलग प्रेम संबंध देखने को मिलेंगे। एक ओर नाओमिका सरन का किरदार होगा और दूसरी ओर प्रगति श्रीवास्तव का। ऐसे में फिल्म की कहानी को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ रही है।

सूत्र ने बताया कि फिल्म की ज्यादातर शूटिंग पूरी हो चुकी है। केवल कुछ दिनों का काम बाकी है। इसके बाद निर्माण कार्य और अन्य तैयारियां पूरी की जाएंगी। माना जा रहा है कि फिल्म को साल 2026 के आखिर तक सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है।

प्रगति श्रीवास्तव की बात करें तो इससे पहले उन्होंने साउथ फिल्मों में काम किया है और धीरे-धीरे हिंदी फिल्म जगत में भी अपनी पहचान बना रही हैं। वह पहले प्रकाश झा की जनादेश और आनंद एल राय की नखरेवाली में काम कर चुकी हैं। अब इस नई फिल्म के जरिए वह बड़े स्तर पर दर्शकों के सामने आएंगी।

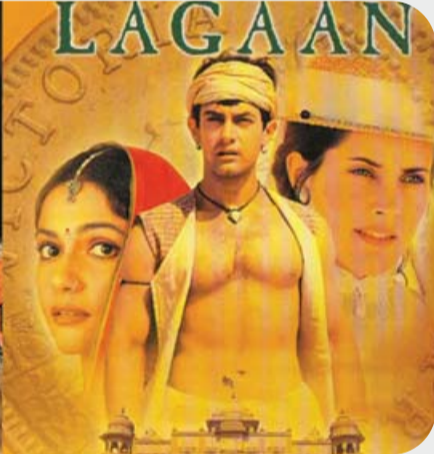
दूसरी ओर, नाओमिका सरन भी लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। वह हिंदी फिल्म जगत के बेहद चर्चित परिवार से ताल्लुक रखती हैं। नाओमिका, हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार माने जाने वाले राजेश खन्ना और मशहूर अभिनेत्री डिंपल कपाडिया की नातिन हैं। उनकी मां रिंकी खन्ना भी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ऐसे में नाओमिका की फिल्मी शुरुआत को लेकर पहले से ही काफी चर्चा बनी हुई है।

वहीं वेदांग रैना भी अपने करियर के महत्वपूर्ण दौर में हैं। उनकी एक और बहुप्रतीक्षित फिल्म में वारस आऊंगा जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में उनके साथ शरवरी वाघ, नसीरुद्दीन शाह और सिलजीत दोसांज़ जैसे बड़े

कलाकार नजर आएंगे।



जब ‘तारा सिंह’ ने हैंडपंप उखाड़ मचाया गदर और ‘भुवन’ ने बचाया तीन गुना लगान



संघर्ष को दिखाया गया। हालांकि, शुरुआत में कई लोगों को लगा कि क्रिकेट पर बनी इतनी लंबी फिल्म शायद नहीं चलेगी, लेकिन रिलीज के बाद इसकी कहानी, म्यूजिक और इमोशनल क्लाइमैक्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया।

‘गदर’ ने सिंगल स्क्रीन थिएटरों में भीड़ का नया रिकॉर्ड बनाया

जहां फिल्म ‘गदर’ ने सिंगल स्क्रीन थिएटरों में भीड़ का नया रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं ‘लगान’ ने भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। दरअसल, फिल्म को 2002 में ऑस्कर के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नामिनेशन मिला और ये भारतीय फिल्मों के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हुई।

सनी देओल और आमिर खान के करियर को मिली नई दिशा

दरअसल, इन फिल्मों ने सनी देओल और आमिर खान के करियर की दिशा भी तय की। इसके साथ ही, सनी देओल मास हीरो के रूप में और मजबूत हुए, जबकि आमिर खान कंटेंट-ड्रिवन और सिनेमा के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हो गए। बता दें, 25 साल बाद भी ‘गदर’ और ‘लगान’ की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि एक फिल्म ने जनता का दिल जीता और दूसरी ने दुनिया का सम्मान। 15 जून 2001 सिर्फ 2 फिल्मों की रिलीज डेट नहीं थी, बल्कि हिंदी सिनेमा के दो अलग-अलग रास्तों की शुरुआत थी।

सनी देओल और आमिर खान की ये कहानी बेहद दिलचस्प है, जहां दोनों ने अपने-अपने कड़ी मेहनत और लगन से अमित छाप छोड़ी है। एक तरफ सनी की सरलता और जज्बा, तो दूसरी ओर आमिर की चमक और टैलेंट ने उन्हें जनता के दिलों में खास जगह दी है। 15 जून 2001 हिंदी सिनेमा के इतिहास की उन चुनिंदा तारीखों में शामिल है, जब 2 बिल्कुल अलग फिल्मों ने एक साथ रिलीज होकर इतिहास रच दिया। बता दें, एक तरफ थी सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार ‘गदर: एक प्रेम कथा’, तो दूसरी ओर आमिर खान की ‘लगान’। इसमें सबसे मजेदार बात ये है कि दोनों फिल्मों एक ही दिन सिनेमाघरों में आईं, लेकिन दोनों का रास्ता और दर्शकों पर असर बिल्कुल अलग था।

देशभक्ति, प्यार और गुस्से का ऐसा कॉम्बो

‘गदर’ में सनी देओल के तारा सिंह ने देशभक्ति, प्यार और गुस्से का ऐसा कॉम्बो था कि दर्शक सीटियां बजाते पंजोर हो गए। फिल्म का हैंडपंप वाला सीन आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार सीन में गिना जाता है। रिलीज के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और अपने दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हो गई। तो वहीं दूसरी ओर, ‘लगान’ ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। लगभग 4 घंटे लंबी इस फिल्म में क्रिकेट, गांव की कहानी और अंग्रेजों के खिलाफ

टीवी इंडस्ट्री में सफलता रातोंरात नहीं मिलती धैर्य और लगातार मेहनत ही असली चाबी है : अद्रिजा रॉय



टीवी इंडस्ट्री की चमक-दमक के पीछे की सच्चाई को लेकर अभिनेत्री अद्रिजा रॉय ने अपने विचार रखे। अद्रिजा रॉय ने कहा, टीवी इंडस्ट्री में काम की गति बहुत तेज होती है। कई बार ऐसा होता है कि आज किसी एपिसोड की शूटिंग होती है और वह अगले ही दिन या बहुत कम समय में टीवी पर प्रसारित हो जाता है।

इस तेज रफ्तार में कलाकारों को हर समय तैयार रहना पड़ता है और अपने किरदार को पूरी एनर्जी के साथ निभाना होता है। हर कॉल टाइम पर, हर शूटिंग शेड्यूल में बहुत बड़ी प्रोडक्शन टीम काम करती है, और कलाकार को इन सबके बीच संतुलन बनाए रखना होता है। ऐसे माहौल में शांत और फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम कई बार असर को कम कर सकता है।

उन्होंने कहा, टीवी इंडस्ट्री में सफलता तुरंत नहीं मिलती। कई लोग सोचते हैं कि एक अच्छा सीन या एक अच्छा प्रदर्शन उन्हें रातोंरात पहचान दिला देगा, लेकिन वास्तविकता अलग है। टीवी में नाम कमाने के लिए

लगातार समय देना पड़ता है। एक-दो अच्छे सीन से लोकप्रियता मिल सकती है, लेकिन स्थायी सफलता की चाबी को लगातार मेहनत और धैर्य ही है। सोशल मीडिया पर भले ही कोई कलाकार जल्दी वायरल हो जाए, लेकिन टीवी इंडस्ट्री में पहचान धीरे-धीरे बनती है और समय के साथ मजबूत होती है।

अद्रिजा रॉय ने लोकप्रियता और सफलता के बीच फर्क को समझते हुए कहा, लोकप्रियता अक्सर अस्थायी होती है, जो किसी वायरल सीन, चर्चा या सोशल मीडिया ट्रेंड से जल्दी मिल सकती है। यह लंबे समय तक नहीं टिकती। दूसरी ओर सफलता एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें लगातार काम करना, अपने अभिनय को बेहतर बनाना और हर किरदार में सुधार लाना जरूरी होता है।

जो लोग इस इंडस्ट्री में स्थायी रूप से सफल होना चाहते हैं, उन्हें समझना होगा कि सिर्फ चर्चा में रहना काफी नहीं है, बल्कि अपने काम में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा, धैर्य मेरे लिए एक सोचने का तरीका बन गया है। धैर्य ने मुझे अपने काम के प्रति ज्यादा गंभीर और शांत बनाया है। अब मैं हर सीन को जल्दीबाजी में नहीं करती, बल्कि उसे समझकर और समय देकर निभाने की कोशिश करती हूँ।



रोजाना कहीं आने-जाने के दौरान त्वचा को प्रदूषण और टैन से बचाने के लिए असरदार तरीके

रोजाना कहीं भी आते-जाते हुए प्रदूषण और सूरज की किरणों का सामना करना पड़ता है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रदूषण के कण और सूरज की किरणें त्वचा की चमक को कम कर सकती हैं और टैनिंग का कारण बन सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी त्वचा को इन समस्याओं से बचा सकते हैं और त्वचा की देखभाल सही तरीके से कर सकते हैं।

धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाएं

घर से कहीं भी बाहर जाते समय हमेशा एक अच्छी गुणवत्ता वाली धूप से बचाने वाली क्रीम लगाएं, जिसे सनस्क्रीन कहा जाता है। यह आपको सूरज की किरणों से बचाएगी और टैनिंग को रोकने में मदद करेगी। इस क्रीम को हर 2-3 घंटे में फिर से लगाएं, खासकर अगर आप लंबे समय तक बाहर रह रहे हैं। ध्यान दें कि क्रीम में सूरज से बचाने की अच्छी क्षमता हो, ताकि यह दिनभर प्रभावी रहे।

चेहरे को कपड़े से ढकें

अगर संभव हो तो अपने चेहरे को एक स्काफ या टोपी से ढकें। यह न केवल

धूप से, बल्कि प्रदूषण से भी बचाव करेगा। अगर आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं तो चेहरे पर कपड़ा या मास्क भी पहन सकते हैं, जो आपके चेहरे को ढकता है और धूल-मिट्टी को रोकता है। इसके अलावा अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट का उपयोग करें, जिससे आपका चेहरा सुरक्षित रहेगा और प्रदूषण का असर कम होगा।

त्वचा को नमी दें

प्रदूषण आपकी त्वचा को सूखा और बेजान बना सकता है, इसलिए कहीं भी जाने से पहले एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं। यह आपकी त्वचा को नमी देगा और उसे मुलायम बनाएगा। अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो हल्का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर चुनें, जबकि सूखी त्वचा वालों के लिए क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर बेहतर रहेगा। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहेगी, जिससे आप हर समय ताजा महसूस करेंगे।

हल्का मेकअप करें

अगर आप रोजाना कहीं भी जाएं तो भारी मेकअप करने से बचें, क्योंकि यह प्रदूषण के संपर्क में आने पर आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। हल्का और प्राकृतिक मेकअप ही करें, जैसे कि हल्की क्रीम, काजल और लिप बाम। इससे आपकी त्वचा को हवा लगने का मौका मिलेगा और वह स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा मेकअप के उत्पादों में एसपीएफ हो तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वे भी आपकी धूप से सुरक्षा कर सकेंगे।

रोजाना सुबह और रात को अपने चेहरे को साफ करें, ताकि सारी गंदगी और प्रदूषण के कण हट जाएं। हफ्ते में 2 बार हल्का स्क्रब करें, ताकि मृत त्वचा हट जाए और त्वचा ताजगी महसूस करे। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपनी त्वचा को प्रदूषण और टैनिंग से बचा सकते हैं और उसे स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इससे त्वचा में एक अंदरूनी निखार आएगा और कभी भी चेहरा डल नहीं दिखेगा।

खास खबर

रायगढ़ जिले में 26 नवीन पीडीएस भवनों को मिली स्वीकृति

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में ग्रामीण विकास और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को निरंतर गति मिल रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के छह विकासखंडों की 26 ग्राम पंचायतों में नवीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भवनों के निर्माण हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से 3 करोड़ 58 लाख 84 हजार रुपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में स्वीकृत यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन भवनों के निर्माण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यक्षमता बढ़ेगी तथा ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत कृषि उत्पादों के संग्रहण तथा रायगढ़ एवं तमनार विकासखंड की चार-चार ग्राम पंचायतों में 59.20-59.20 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

निर्माण की धीमी गति पर बिफरे उप मुख्यमंत्री साव, 2 ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव द्वारा सड़कों व पुलों के निर्माण की धीमी गति पर गहरी नाराजगी जाहिर करने और ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश के बाद विभाग ने दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग ने कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले 8 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। वहीं पूर्व में दो ठेकेदारों को जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब का परीक्षण कर ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता से प्रतिवेदन मंगाया गया है। लोक निर्माण विभाग ने 10 जून को भी राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर केशलूर-जगदलपुर मार्ग में किरंदुल-विशाखापट्टनम रेलवे लाइन के ऊपर केशलूर के पास बन रहे फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज में काम की प्रगति पंजूर किए गए निर्माण कार्यक्रम से काफी पीछे होने और तय किए गए माइलस्टोन के अनुरूप नहीं होने पर ठेकेदार मेसर्स अशाक कुमार मित्तल को नोटिस जारी कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

मर्दापाल में राजमिस्त्री प्रशिक्षण का शुभारंभ

कोंडागांव। कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अविनाश भोई के मार्गदर्शन में ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से एसबीआई आरसेटी, कोंडागांव द्वारा ग्राम पंचायत मर्दापाल में मेसनरी एंड कंक्रिट वर्क राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यह प्रशिक्षण दिनांक 13 जून 2026 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें कुल 35 प्रशिक्षार्थियों का पंजीयन कर नियमित कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को भवन निर्माण कार्य, तकनीकों का व्यावहारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

बस्तर के उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार

श्रीकंचनपथ समाचार

जगदलपुर। बस्तर जिले के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने तथा जिले के निर्यात परिदृश्य को एक नई दिशा देने के लिए आज कलेक्टर कार्यालय के प्रेरणा हॉल में जिला निर्यात संवर्धन समिति की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शिर्ष्यात केंद्र के रूप में जिले (डीईएच) पहल के अंतर्गत बुलाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बस्तर जिले से निर्यात को तीव्र गति से बढ़ावा देना, नए निर्यातकों की संख्या में वृद्धि करना तथा निर्यात के मार्ग में आने वाली व्यावहारिक व तकनीकी बाधाओं का त्वरित निवारण करना है।



समुद्र कृषि उत्पाद, मूल्यवान वनोपज, पारंपरिक हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) तथा अन्य विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक बाजारों में सही स्थान दिलाने के लिए सभी संबंधित सरकारी विभागों और अग्रणी संस्थाओं के मध्य आपसी समन्वय और समन्वित प्रयासों पर विशेष बल दिया। इस दौरान बस्तर जिले में निर्यात की वर्तमान स्थिति को रेखांकित करते हुए मुंबई से आए विदेश व्यापार के संयुक्त महानिदेशक डॉ

तथा प्रमुख निर्यात क्लस्टरों के विकास हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रमों के आयोजन करने का निर्णय सीधे कलेक्टर श्री आकाश छिकारा द्वारा लिया गया। इसके साथ ही, पहली बार निर्यात के क्षेत्र में कदम रखने वाले नए उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों तथा स्व-सहायता समूहों को अनिवार्य आईईसी प्राप्त कराने तथा उन्हें पूरी निर्यात प्रक्रिया से सुगमता से जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। व्यापारिक सुगमता को और बढ़ाने के उद्देश्य से बैठक में भारत सरकार की निर्यात संवर्धन मिशन के तहत संचालित होने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा वित्तीय सुविधाओं की विस्तृत जानकारी साझा की गई। वहां उपस्थित अधिकारियों और स्थानीय उद्यमियों को अत्याधुनिक ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होने वाली सेवाओं, वैश्विक बाजारों की वास्तविक स्थिति, निर्यात वित्त, विदेशी बाजारों तक पहुंच सहायता और अन्य प्रोत्साहन उपायों से विस्तार से अवगत कराया गया ताकि बस्तर के व्यवसायी अंतरराष्ट्रीय मानकों का लाभ उठा सकें। इस उच्च स्तरीय बैठक में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास

जिला प्रशासन बालोद द्वारा मिशन अंकुर की शुरुआत

श्रीकंचनपथ समाचार

बालोद। बालोद को हरा-भरा बनाने जिला प्रशासन की अनूठी पहल मिशन अंकुर की शुरुआत आज संयुक्त जिला कार्यालय के जनदर्शन कक्ष में कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने की। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उन्हें सीड बाल प्रदान कर खाली जगहों में सीड बाल फेंकने प्रोत्साहित भी किया। शुभारंभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल, दुर्ग वनमंडल के वनमंडलाधिकारी दीपेश कपिल, जिला पंचायत के सीईओ सुनील चंद्रवंशी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। सीड बॉल मिट्टी, खाद और विभिन्न उपयोगी वृक्षों के बीजों को मिलाकर बनाई गई एक छोटी सी गेंद होती है। इसे रोपने के लिए गड्ढा खोदने की आवश्यकता नहीं होती। इसे हाई ट्रेंच, जंगल, खाली जमीनों, पहाड़ियों या बंजर इलाकों में फेंक दिया जाता है। मानसून की बारिश पड़ते ही यह अंकुरित होकर एक पौधे का रूप ले लेती है।



मिशन अंकुर के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रजातियाँ (जैसे- नीम, पीपल, बरगद, मुनगा, करंज, कटहल, इमली आदि) के बीजों का उपयोग कर सीड बॉल का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अंतर्गत स्व-सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा 02 लाख 50 हजार नग एवं वन विभाग के द्वारा 01 लाख नग कुल 03 लाख 50 हजार नग सीड बॉल बनाया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

फलों जैसे- नीम, पीपल, बरगद, मुनगा, करंज, कटहल, इमली आदि के बीज रहते हैं, उसे हमें सुखाना है और मिट्टी से लपेट कर एक सीड बाल का रूप देना है, तथा खाली स्थानों पर उसे फेंकना है। जिससे वह बाल बारिश के पानी को सोखकर अंकुरित हो सकेगा और पौधे का रूप ले लेगा। उन्होंने स्वसहायता समूह की दीदीयों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके सहयोग से सीड बाल तैयार किया गया है। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जनदर्शन में पहुंचे लोगों को सीड बाल प्रदान कर उन्हें जिले को हरभरा बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने प्रोत्साहित भी किया। शुभारंभ कार्यक्रम को पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल और दुर्ग वनमंडल के वनमंडलाधिकारी दीपेश कपिल ने भी संबोधित कर लोगों को पेड़ का महत्व बताते हुए सीड बाल के माध्यम से जिले को हरभरा बनाने प्रोत्साहित किया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि हम दो तरह से पेड़ उगा सकते हैं।

दुर्गम पंडो बस्ती तक पहुंची स्वास्थ्य सेवाएं 54 ग्रामीणों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप दूरस्थ एवं विशेष पिछड़ी जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बलरामपुर जिले में विशेष स्वास्थ्य एवं जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत चेरा के आश्रित पंडो बाहुल्य हरिजन पारा में वृद्ध स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई तथा संभावित महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय किए गए। आयोजित शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 54 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर के दौरान 17 लोगों का रक्तचाप परीक्षण, 17 लोगों की शुरुआत तथा 46 लोगों की हीमोग्लोबिन जांच की गई। इसके अलावा

खुजली से प्रभावित 15 मरीजों, दाद से पीड़ित 6 मरीजों और दर्द संबंधी समस्या वाले 5 मरीजों का उपचार कर आवश्यक दवाइयां वितरित की गई। साथ ही 5 लोगों की कुछ रोग संबंधी जांच भी की गई। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल के उपयोग, मौसमी बीमारियों से बचाव तथा समय पर उपचार के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। जलजनित रोगों की रोकथाम के लिए गांव में उपयोग किए जा रहे 25 पेयजल स्रोतों का जल शुद्धीकरण भी किया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने ग्रामीणों को किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में तत्काल मितानिन अथवा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संपर्क करने तथा आवश्यकता पड़ने पर निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उपचार लेने की सलाह दी।

उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने 99 लाख 78 हजार रूपए के सड़क डामरीकरण कार्य का भूमिपूजन किया

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर संजुदेवी राजपूत ने कोरबा के रविशंकर नगर जोन अंतर्गत रविशंकर नगर में 99 लाख 78 हजार रूपये की लागत से होने जा रहे बिटुमिन सड़क निर्माण व डामरीकरण कार्य का भूमिपूजन किया। उन्होंने भूमिपूजन पट्टिका का अनावरण एवं नारियल तोड़कर कार्य का शुभारंभ कराया तथा कार्य के दौरान गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखने एवं शीघ्र कार्य को पूरा करने के निर्देश



अधिकारियों को दिये। नगर पालिक नगर कोरबा द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल नगर अंतर्गत रविशंकर नगर स्थित मेडिको से दादर नाला पुल तक

श्री देवांगन एवं महापौर श्रीमती संजुदेवी राजपूत के हाथों किया गया। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य हितानंद अग्रवाल, पार्षद नरेंद्र देवांगन, वार्ड पार्षद अब्दुल रहमान एवं सुनीता चौहान, राकेश वर्मा, चन्द्रलोक सिंह, प्रताप सिंह कंवर आदि के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ावा देश का सम्मान-इस अवसर पर अपने उद्घोषन में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्षों पूर्ण हो चुके हैं, इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में

ऐतिहासिक कार्य किये तथा विश्व स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आशीर्वाद से नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न मदों के अंतर्गत 1000 करोड़ रूपये के विकास कार्य स्वीकृत कराये जा चुके हैं तथा अभी और विकास कार्य स्वीकृत होने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि निगम क्षेत्र की सभी प्रमुख सड़कों के डामरीकरण व जैंगनीदार के कार्य स्वीकृत हैं, जैसे- जैसे डामर की उपलब्धता होती जा रही है, सड़क डामरीकरण के कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैं। बिना भेदभाव के हो रहे

विकास कार्य-इस अवसर पर महापौर संजुदेवी राजपूत ने अपने उद्घोषन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नगरीय प्रशासन मंत्री व उप मुख्यमंत्री अरुण साव तथा उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन व आशीर्वाद से निगम क्षेत्र में व्यापक रूप से विकास कार्य हो रहे हैं तथा सभी 67 वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री देवांगन एवं मुझे कोरबा की जनता का जो भरपूर आशीर्वाद मिला, उन्होंने हम पर जो विश्वास जताया, वह विश्वास हमेशा बना रहेगा।

कुपोषण और लर्निंग गैप दूर करने सुकमा जिला प्रशासन की अभिनव पहल

सशक्त आंगनबाड़ी अभियान से संवरेगा नौनिहालों का भविष्य

श्रीकंचनपथ समाचार



आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाएंगे शिक्षक
अभियान के तहत अब स्कूलों के शिक्षक सप्ताह में एक दिन आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर बच्चों के साथ समय बितायेंगे और खेल-खेल में उन्हें प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ेंगे। इससे बच्चों की सीखने की क्षमता विकसित होगी, लर्निंग गैप कम होगा तथा वे विद्यालयी शिक्षा के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकेंगे। शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच यह समन्वित प्रयास विशेष रूप से ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बच्चों के उज्वल भविष्य का मजबूत आधार

कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की सदस्य दीपिका सोरी ने कहा कि यह अभियान सारी को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके बेहतर भविष्य के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों तक पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास से जुड़ी अनेक योजनाओं के माध्यम से माताओं और बच्चों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

के तहत पुराने आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन कर उन्हें बेहतर सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति और भवन निर्माण भी किया जाएगा, जिससे बच्चों और माताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकें। नगर पालिका अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम ने बच्चों को राष्ट्र का भविष्य बताते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों से प्रत्येक बच्चे को अपने परिवार के सदस्य की तरह मार्गदर्शन और स्नेह

देने का आह्वान किया। वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री धनीराम बारसे ने कहा कि बच्चों के समग्र विकास की मजबूत नींव आंगनबाड़ी केंद्रों में ही रखी जाती है। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को

कलेक्टर ममगाई ने आमजन की समस्याएं सुनीं

बेमेतरा। जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाले जनदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत आज कलेक्टर ने जनदर्शन का आयोजन किया गया। जनदर्शन में कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। जनदर्शन के दौरान नागरिकों ने अपनी विभिन्न मांगों, शिकायतों एवं समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दूरभाष पर एवं समक्ष बुलाकर प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। कई प्रकरणों का समाधान मौके पर ही किया गया।

SAIRAM
Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़कों की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्वेन्स एवं हार्डलैट उपलब्ध यहां उचित व्याज दर पर धरित्री स्वी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower, Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919 K. Satyanarayan

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 22964330

Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर



स्कूल खुलने पर मुख्यमंत्री ने बच्चों को दी सफलता की सीख

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 16 जून से नए शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें पूरी लगन और उत्साह के साथ पढ़ाई करने का संदेश दिया है। विद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने का स्थान नहीं, बल्कि बच्चों के सपनों को आकार देने और उज्वल भविष्य की नींव रखने का माध्यम है। उन्होंने बच्चों से पूरे आत्मविश्वास, अनुशासन और उत्साह के साथ नियमित रूप से विद्यालय जाने तथा मन लगाकर पढ़ाई करने का आग्रह किया।

नीट-यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को होगी आयोजित

अम्बिकापुर। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 परीक्षा का आयोजन आगामी 21 जून को जिले में 13 परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा, जिसमें 5212 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कलेक्टर अजीत वसंत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल के साथ पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, विद्युत, बैठने की व्यवस्था, शौचालयों की साफ-सफाई तथा अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को परीक्षा के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर ने परीक्षा केंद्र पर दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने तथा यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

सोलर पैनलों की स्थापना से लेकर देखभाल करेंगी सोलर दीदियां, 35 महिलाओं को मिला प्रशिक्षण

श्रीकंचनपथ समाचार

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सराहनीय व अभिनव शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत वंदे मातरम् संकुल स्तरीय संघ से जुड़ी 35 महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों को 'सोलर दीदी' के रूप में विशेष तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये महिलाएं गांवों में सौर ऊर्जा संयंत्रों और उपकरणों की स्थापना, संचालन

तथा उनके रखरखाव व मरम्मत का मोर्चा संभालेंगी। कार्यक्रम में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं को सोलर सिस्टम की बारीकियों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य रूप से सोलर पैनल और सिस्टम की तकनीकी जानकारी, इंस्टॉलेशन (स्थापना) की सही प्रक्रिया, सौर उपकरणों का नियमित रखरखाव, खराबी आने पर समस्या निवारण के व्यावहारिक तौर-तरीके बताए गए।

इस पहल से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा सेवाओं की स्थानीय स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अब



ग्रामीणों को अपने सौर उपकरणों को सुधरवाने के लिए शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि उनके अपने

महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में मील का पत्थर साबित होगा। ये सोलर दीदियां ग्रामीण घरों और स्थानीय संस्थानों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सीधे तौर पर सहयोग करेंगी। इससे जहां एक ओर ग्रामीण अंचलों में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा का तेजी से विस्तार होगा, वहीं दूसरी ओर सौर संयंत्रों की स्थापना से मिलने वाले कमीशन और तकनीकी सर्विस चार्ज के माध्यम से इन महिलाओं की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जिला पंचायत कबीरधाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक

अग्रवाल ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण और नवाचारपूर्ण कदम है। यह अनूठी परियोजना महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण (हरित ऊर्जा संवर्धन) और सतत विकास के लक्ष्यों को एक साथ हासिल करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश कर रही है। आने वाले समय में ये सोलर दीदियां न केवल कबीरधाम के गांवों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगी, बल्कि समाज की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का बड़ा स्रोत बनेंगी।

जैविक कृषि कार्यशाला सह कृषक सम्मेलन में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष

नवाचार से निखरी सुरगी की छवि, जैविक एवं प्राकृतिक खेती से समृद्ध होगा किसान : रमन सिंह

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव जिला के कृषि विज्ञान केंद्र, सुरगी में आयोजित जैविक कृषि कार्यशाला सह कृषक सम्मेलन में शामिल हुए। खुमरी पहनाकर उनका आत्मीय स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभिन्न कृषि एवं जैविक उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन किया तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।



उन्नत खेती, नवाचार, उत्पादन क्षमता वृद्धि, कम लागत में बेहतर उत्पादन तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग के कारण सुरगी मॉडल प्रदेशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ड्रोन एवं आधुनिक मशीनों के माध्यम से कृषि कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों को नई तकनीकों का लाभ मिल रहा है।

प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़ते हुए गोबर खाद एवं जैविक खाद का अधिकारिक उपयोग करना चाहिए।

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव जिले में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र, सुरगी आज प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। यहां छह राज्यों के विद्यार्थी हैं। ऐसे में किसानों को जैविक एवं

उन्होंने बताया कि सुरगी उनका गोद ग्राम है, जहां निरंतर विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। सुरगी-खरखरा डायवर्सिन नहर लाईनिंग का 19 करोड़ रुपए का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। वहीं शिवनाथ डायवर्सिन से जुड़ी मुख्य नहर एवं लघु नहरों का कार्य 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

उन्होंने बताया कि सुरगी सौर चलित सिंचाई परियोजना, कृषि महाविद्यालय,

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हाई स्कूल, विद्युत उपकेन्द्र, शौचालय उन्नयन तथा विभिन्न अधोसंरचनात्मक कार्यों सहित ग्राम पंचायत सुरगी में करोड़ों रुपए के विकास कार्य संपादित किए गए हैं।

सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि जैविक उत्पादों की बाजार में मांग लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में जिले में लगभग 550 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है, जिसका प्रमाणिकरण भी कराया जा रहा है। उन्होंने ग्राम भरंगंव की महिला स्व-सहायता समूह द्वारा प्राकृतिक उत्पाद निर्माण एवं विपणन की सराहना की।

समाजसेवी कोमल सिंह राजपूत ने कहा कि सुरगी में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ मिल रहा है।

कलेक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि खरीफ वर्ष 2025 में धान बेचने वाले 1,24,101 किसानों को 1,484 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 454.12 करोड़ रुपए की अंतर राशि का भुगतान भी किया गया। खरीफ 2026 में धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, लघुधान्य एवं कपास की खेती करने वाले कृषकों को 15 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।

प्रशासनिक सेवाओं का प्रथम उद्देश्य जनसेवा : मुख्यमंत्री साय



श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन प्रशिक्षु अधिकारियों ने सीजन मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रशासनिक सेवा जनसेवा का सबसे प्रभावी माध्यम है। एक प्रशासनिक अधिकारी के निर्णय हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए प्रत्येक निर्णय में जनहित सर्वोपरि होना चाहिए। लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना महत्व तभी है, जब उसका उपयोग समाज और आम जनजीवन में सकारात्मक के लिए किया जाए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के महानिदेशक एवं अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, संचालक टीसी महावर तथा संयुक्त संचालक प्रणव सिंह उपस्थित थे।

सफलता तथा राज्य के विकास की यात्रा से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता, जनजातीय परंपराओं और विकास के नए अवसरों पर भी अपने अनुभव साझा किए। प्रशिक्षु अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें सुकमा, बीजापुर, जशपुर, सरगुजा और कोरिया जिलों के भ्रमण का अवसर मिला। यहां के लोगों के स्नेह, जनजातीय परंपराओं ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी गोकुल आरके, वी यशवंत नायक एवं ईशांत जायसवाल छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तीनों अधिकारियों को छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित हुआ है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूर्ण होने पर तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ

श्रीकंचनपथ समाचार

राजनांदगांव। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा 15 से 17 जून 2026 तक राजनांदगांव के महावीर चौक स्थित फ्लॉइओवर के नीचे केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आधारित तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का शुभारंभ सांसद संतोष पाण्डेय एवं महापौर मधुसूदन यादव ने किया।

इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विभिन्न विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शित जानकारी का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही।

फोटो प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी एवं



जनहितकारी नेतृत्व में देश तथा छत्तीसगढ़ में हुए विकास कार्यों और शासन की योजनाओं के प्रभाव को आकर्षक चित्रों एवं जानकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्शनी में किसान कल्याण, गरीब कल्याण, अधोसंरचना विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल इंडिया, महिला

सशक्तिकरण, युवा विकास तथा सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण जैसे विभिन्न विषयों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में 4.3 लाख करोड़ रुपए की राशि अंतरण, किसानों को लागत से कम से कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य

(एमएसपी) की गारंटी, कृषि निर्यात में वृद्धि तथा लगभग 2 करोड़ किसानों एवं 3 लाख व्यापारियों के ई-नाम पोर्टल से जुड़ने संबंधी जानकारी प्रदर्शित की गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ पक्के आवासों के निर्माण, सेमीकंडक्टर निर्माण, मुफ्त राशन योजना तथा 9 करोड़ लाभार्थियों के पोषण ऋय जैसे जनकल्याणकारी कार्यों को भी दर्शाया गया है।

देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए प्रयासों को भी प्रदर्शनी में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। अधोसंरचना विकास के अंतर्गत विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज, समुद्र पर निर्मित अटल सेतु, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के 1.46 लाख किलोमीटर से अधिक विस्तार तथा वंदे भारत स्टीपर ट्रेनों की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्रदर्शित किया गया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दो पुनर्वासित जोड़ों के साथ 17 जोड़ों ने गृहस्थ आश्रम में किया प्रवेश

श्रीकंचनपथ समाचार

जगदलपुर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह' राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक कल्याणकारी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब, निराश्रित, और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना मुख्य रूप से सामूहिक विवाह के माध्यम से सम्पन्न होती है, जिससे गरीब परिवारों पर विवाह का भारी आर्थिक बोझ कम हो सके और फिजूलखर्च पर रोक लगे।

जगदलपुर स्थित पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार (टाउन हॉल) में सोमवार को मुख्यमंत्री नेताजी पुलिस अकादमी चंदखुरी के ऊपर अक्षत और पुष्प वर्षा कर उन्हें सुखी और समृद्ध दंपत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। इस विवाह समारोह की सबसे मंत्रोच्चार और शहनाई की गूंज के



बीच कुल 17 जोड़े सदा-सदा के लिए एक-दूसरे के साथ दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जगदलपुर विधायक श्री किरण सिंह देव ने नवविवाहित जोड़ों के ऊपर अक्षत और पुष्प वर्षा कर उन्हें सुखी और समृद्ध दंपत्य जीवन अपनाकर समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। विधायक श्री किरण सिंह देव ने इन जोड़ों की

सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार की पुनर्वासि नीति के तहत ऐसे कदमों से बस्तर में शांति और खुशहाली के एक नए युग की शुरुआत हो रही है।

विवाह समारोह को संबोधित करते हुए जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की महत्ता पर प्रकाश डाला और कहा कि बेटियों का विवाह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। हमारी संवेदनशील सरकार के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रघुवाड़े जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत विवाह हो रहा है। इस योजना के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का सम्मानपूर्ण विवाह कराना समाज का सबसे पुनीत कार्य है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलती है।

33 प्रशिक्षु डीएसपी का बुनियादी प्रशिक्षण प्रारंभ

नैतिकता से बड़ा कोई बल नहीं होता : गृहमंत्री शर्मा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में वर्ष 2021 एवं वर्ष 2024 के छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 33 उप पुलिस अधीक्षकों के बुनियादी प्रशिक्षण का नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी में शुभारंभ हुआ। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आप सभी ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण से इस प्रतिष्ठित सेवा में स्थान प्राप्त किया है। यह केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि एक सेवा, एक दायित्व, और एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस समारोह में पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम, अति. पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण दीपाशु काबरा उपस्थित हुए। साथ ही अकादमी के महानिदेशक अजय यादव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव, अति. पुलिस अधीक्षक सोनिया उके एवं अकादमी के समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित थे। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज का



दिन न केवल आप सभी नव-नियुक्त उप पुलिस अधीक्षकों के लिए, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी ने कठिन परिश्रम, लगन और समर्पण के बल पर इस प्रतिष्ठित पद को प्राप्त किया है। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नैतिकता से बड़ा कोई बल नहीं होता, आज नवीन समाज की आवश्यकता को समझना और उसके आधार पर संवेदनशीलता पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। पुलिस केवल कानून का पालन करवाने वाली संस्था

नहीं, बल्कि समाज की रक्षा करने वाली एक शक्ति है। हमें न केवल अपराध को रोकना है, बल्कि जनता में विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करना है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस की पहचान न केवल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में है, बल्कि राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा एवं न्याय दिलाने में भी है। हमारी चुनौती केवल अपराधों पर नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें समाज के विश्वास को बनाए रखना भी उतना

ही आवश्यक है। पुलिसिंग आज केवल शारीरिक साहस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग, साइबर अपराधों से निपटने की दक्षता और सामुदायिक जुड़ाव भी शामिल है।

इस अवसर पर राज्य के पुलिस महानिदेशक अरूण देव गौतम द्वारा कहा गया कि आज का दिन छत्तीसगढ़ पुलिस परिवार के लिए अत्यंत गौरव और उत्साह का अवसर है। आपने कठिन प्रतियोगी परीक्षा, अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर यह स्थान प्राप्त किया है। आज से आपका जीवन केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और कानून के शासन को सुदृढ़ करने के महान दायित्व से जुड़ रहा है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक श्री यादव ने कहा कि नेताजी पुलिस अकादमी चंदखुरी में विभिन्न जिलों के 33 अभ्यर्थी उप पुलिस अधीक्षक बुनियादी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हुये हैं। अधिकांश प्रशिक्षु इंजीनियर हैं। संस्था के निदेशक द्वारा उप. पुलिस अधीक्षकों के 02 वर्षों के पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम को विस्तृत जानकारी दी गई।



टाइगर रिजर्व और अभयारण्य तत्काल बंद, 1 अक्टूबर तक सफारी भी नहीं

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मानसून के आगमन और वन्यजीवों के प्रजनन काल को देखते हुए, हर साल की तरह इस वर्ष भी देश के अधिकांश टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में जंगल सफारी 15 जून से 1 अक्टूबर तक साढ़े 3 महीने के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। पीसीसीएफ एवं वन बल प्रमुख अरुण पांडेय

ने बताया, हर साल मानसून के पहले टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों को बंद कर दिया जाता है। 2 अक्टूबर 2026 से जंगल सफारी और अन्य पर्यटन गतिविधियां दोबारा शुरू की जाएंगी।

वन विभाग के आला अधिकारियों के अनुसार, इस रोक के पीछे दो मुख्य कारण हैं। वर्षा ऋतु के दौरान जंगलों के भीतर आवाजाही कठिन हो जाता है।

इस दौरान वन्यजीवों को एक शांत और प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। संरक्षित वन क्षेत्रों में अचानकमारा टाइगर रिजर्व, उदती-सोतानदी टाइगर रिजर्व, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य, कांभर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, प्रदेश के अन्य सभी अधिसूचित अभयारण्य और संरक्षित वन क्षेत्र शामिल हैं।

बंद के दौरान वन विभाग चलाएगा विशेष अभियान

पर्यटकों के लिए प्रवेश बंद रहने के दौरान वन विभाग शांत बेटेने के बजाय जंगलों के भीतर कई महत्वपूर्ण कार्य संपादित करेगा। अवैध शिकार को रोकने के लिए गश्त तेज की जाएगी और वन्यजीवों की स्थिति मॉनिटरिंग होगी। जंगलों के भीतर प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। आगामी पर्यटन सत्र को ध्यान में रखते हुए सफारी मार्गों, ट्रेकों और रिसॉर्ट्स की मरम्मत व रखरखाव किया जाएगा, ताकि 2 अक्टूबर से पर्यटकों को बेहतर और सुरक्षित अनुभव मिल सके।